26/9/20

अध्याय – 6

जनजातीय लोगों की समस्याएँ
(Problem's of Tribal People)

I. गरीबी (Poverty) :— निसंदेह दीर्घकालिन गरीबी व्यापक गरीबी भारत के इतिहास में शुरू से चली आ रही है। अपनी आर्थिक समस्याएं हल करने और सर्वतोमुखी विकास करने के हमारे प्रयास हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के साथ शुरू हुई है इन्होंने कई मामलों में देश का कायाकल्प किया जैसे :- ठोस औद्योगिकरण, हरित क्रांति जिससे देश में आवश्यकता से अधिक खाद्य पदार्थ पैदा होने लगा, अवसद जीवन आयु में वृद्धि हुई। मध्य वर्ग की समृद्धि में वृद्धि तेजी से हुई हमारे नियोजन का विरोधाभाषा यह है कि वह भारत के गरीबी के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में असफल रहा। गरीबी नीचे स्तर के प्रतिव्यक्ति आय में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है और देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी की रेखा के नीचे की ही गुजर बसर कर रहा है। गरीबी की यह रेखा पहले 3500 रू० के नीचे ही उपभोग स्तर पर थी और बाद में वह संशोधित रूप में 6400 रू० के उपभोग स्तर पर पहुँच गई है।

अतः देश के 41 करोड़ 30 लाख लोगों के लिए जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। विकास एक दूर का सपना-सा है। यह आँकड़ा 1993 है। गरीबी की इस स्थिति के लिए बहुत से पहलू जिम्मेदार हैं। और वे सभी हमारे नियोजन के प्रतिमान और देश की सामाजिक, राजनीतिक संरचना में मौजूद हैं। हमारी योजनाओं में औद्योगिक उन्नति, विशेष रूप से

Scanned with CamScan

Date ___/___/______

विनिर्माण और कृषि पर, आवश्यकता से अधिक बल दिया है। कृषि के क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक बल दिया है। तथा कृषि के क्षेत्र में बड़े पैमाने की सिंचाई योजनाएँ और रासायनिक उर्वरकों आदि को प्रोत्साहित किया है जो वास्तविक रूप से बड़े तथा सम्पन्न किसानों के लिए लाभप्रद है। लेकिन छोटे और गरीब किसानों के लिए नहीं। आमतौर पर यह मान लिया गया है कि औद्योगिक विस्तार, कृषि उत्पादन और रोजगार के अवसरों की वृद्धि से जो लाभ होंगे वे समाज के नीचे से नीचे तक के लोगों तक पहुँचेंगे। यह सर्वोहा असमान जटिल समाज में आय के वितरण जैसी छोटी चीज के आधार पर पूरे समाज में व्याप्त अंतरों को कम करने के सभी प्रयास पूर्णतः उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा। विश्लेषकों ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार ने हस्तक्षेप करने की जितनी भी कोशिश की है जैसे:- भूमि सुधार, कृषिगत आय, और रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से शिक्षा सम्बन्धी बाह्य संरचनाओं जैसे स्कूल, हॉस्टल आदि का निर्माण वे सभी पूरे मन या उत्साह के साथ नहीं की गई। इन सभी पर उद्योगपति और पूंजीपति का ही अन्त तक छाया रहा। और इन्होंने धीरे-धीरे राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया।

इन त्रुटियों के परिणाम स्वरूप चौथी योजना अवधि में और उसके बाद भी ग्रामीण इलाकों की गरीबी हटाने के लिए किसी समूह विशेष को निशाना बनाकर गरीबी हटाने का लक्ष्य ही निर्धारित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भूमि सुधार की जो सबसे जरूरी कार्यवाही कारवाई थी उसकी गरीबी हटाओ कार्यक्रम के अंतर्गत एक आय विशेष और रोजगार पैदा करने की योजनाओं पर बल दिया गया। इनमें जो योजनाएँ शामिल की गई थी- वे रोजगार के अवसर पैदा करने वाली योजनाएँ, "मार्जिन मनी" देकर खेती की, और अतिरिक्त आय के जरिये पैदा करने में मदद कर दी थी। 1980 के प्रारंभिक वर्षों में I.R.D.P

Scanned with CamScanner

Date __/__/____

का विस्तार और सर्वाधिक लाभहीनों तक पहुँचने के लिए उसे कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर बाद में यह स्थिति पर थोड़ा-बहुत प्रभाव डालने में सफल हो सका।

दूसरों की तुलना में अनुसूचित जनजातियों में गरीबी का स्तर चिंताजनक (बहुत अधिक) करने योग्य है 1983 से 1984 के काल में ग्रामीण जनजाति समुदाय में 58.4% व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे थे। जिनमें से लगभग 94% जनजाति के लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। शहरी आबादी में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 31.9% थे 8वीं योजना के दौरान जनजातियों पर काम करने वाले लोगों के अनुसार 1991 में 91.84 लाख जनजाति परिवार गरीबी की रेखा के नीचे थे। I.R.D.P. की एक योजना ने 8वीं योजना में लगभग अवधि में लगभग 42% परिवारों की सहायता की। फिर भी ऐसा कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है जिससे सही रूप से यह जाना जा सके कि जनजातियों के कितने परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर आ सके हैं। I.R.D.P की मूल्यांकन के अनुसार गरीबी की रेखा पार करने वाले परिवारों की प्रतिशत बहुत ही कम है। कार्यकारी समूह का अनुमान था कि गरीबी की रेखा पार करने के लिए प्रति परिवार 8000 रू० का निवेश होना जरूरी था। लेकिन वास्तविक रूप से प्रति परिवार केवल 3481 रू० का निवेश ही किया जा सका। यही नहीं अनुसूचित जनजाति के प्रति परिवार पर जो निवेश किया गया जो वह उन परिवारों पर अनुसूचित जनजाति के नहीं थे किये गए निवेश से भी बहुत कम था। यह भी अनुभव किया गया है कि जनजाति समुदाय के ज्यादातर हिस्सों को दरिद्र बनाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय विकास के बड़े पैमाने के लक्ष्यों को पूरा करने की कारवाई कर रही है। जनजातीय समुदाय धीरे-धीरे एक ऐसी प्रक्रिया का शिकार होता गया जिसमें एक ओर तो उनके साधनों के

Scanned with CamScanner

Date __/__/__

आकार और उत्पादन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से अस्त-व्यस्त हो गया और दूसरी ओर इसके परंपरागत सामुदायिक अधिकारों और आर्थिक मूल आधारों का अपहरण राज्य सरकारों और व्यापारी हितों द्वारा किया गया। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के भूतपूर्व कमिश्नर डॉ॰ बी॰पी॰ शर्मा के अनुसार :- "मौजूदा परिस्थितियों की गहरी जाँच से स्पष्ट है कि इस जन समाज को पाँच स्तरों पर वंचित किया गया है:-

I. साधनों पर जो हमारा परंपरागत अधिकार था उनको मान्यता नहीं दी गई और उनके लिए उन साधनों पर पाबन्दी लगा दी गई।

II. काम करने वालों को उत्पादन के साधनों से अलग किया गया।

III. मजदूरों को उनकी किस्ते नहीं दियी गयी।

IV. उनकी स्वाधिनता का सौदा किया गया।

V. मनोवैज्ञानिक रूप से अपने को हीन और वंचित समझने के लिए विवश होना पड़ा। जिसके फलस्वरूप उनमें अपनी इज्जत और अपनी आत्म सम्मान की भावना समाप्त हो गयी। दूसरे शब्दों में जंगलों से वन-उत्पाद सम्बन्धित उनके पारंपरिक परंपरागत अधिकार पूरी तरह से छीन गए। जनजातियों की अच्छी उपजाऊ जमीनें उन लोगों के हाथों से चली गयी जो उनके समाज के नहीं थे। जनजाति के लोग दिन-प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं। यही नहीं वे बड़ी संख्या में मजदूरी करने लगे हैं और इन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है। स्वयं सरकारी विभाग भी इन्हे उतनी मजदूरी नहीं देते हैं, जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी है। औद्योगिक विकास और सिंचाई की बड़ी-बड़ी योजनाओं के सम्पन्न लोगों को लाभ पहुँचा वही जनजाति के परिवारों को अपने मूल स्थान छोड़ने और विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ा।

Scanned with CamScanner

Date 27 / 03 / 19

कहने का मतलब यह है कि जनजातियों के वन जंगलों से उनके परंपरागत अधिकार धीरे-धीरे छीने गए और जनजातियों की अच्छी जमीनें दूसरे लोगों के हाथों में चली गई, नतीजा यह हुआ कि जनजाति लोग गरीब होते गए। और बड़ी संख्या में मजदूरी के लिए विवश हो गए। बड़ी-बड़ी परियोजनाओं में भी जनजाति परिवारों को विस्थापित होने पर जो मुआवजा भी मिला वह कमजोर व्यवस्था के चलते समय पर नहीं मिल सका। और इन विस्थापितों को पुर्नवास की योजना नहीं बन पाई।

जनजातीय निर्धनता की समस्या का निदान बहुत ही कठिन है परन्तु इनके विकास के लिए सरकार की ओर से प्रयास किये जा रहे हैं। गरीबी हटाओ कार्यक्रम भी अनुसूचित जनजातियों को अधिक नहीं मिला है। सार्वजानिक वितरण प्रणाली में सुधार रोजगार दिलाने के कार्यक्रम आदि। अनेक उपाय सरकार द्वारा किये जा रहे हैं। उन्हें शोषण से मुक्त करने के लिए कानून बनाए गए है तथा शिक्षा की व्यवस्था अलग से की जा रही है। शिक्षण संस्थानमें एवं नौकरि-यों में आरक्षण दिया जा रहा है। इन प्रयासों के फल-स्वरूप आदिवासीयों की स्थिति में काफी सुधार आया है। किन्तु अभी और भी अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।

STOP